हर्षा भोगले ने वैभव की तारीफ की

Page-04

tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

आलिया भट्ट बनी अल्फा भट्ट

Page-05

नीति आयोग बैठक
स्किल और उद्यमिता पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता और राज्यों के सहयोग से विकास को गति देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे उत्पादक रोजगार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है।बैठक में निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। नीति आयोग ने राज्यों को सफल विकास मॉडल साझा करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का सुझाव दिया। कई राज्यों ने कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में अपने अनुभव प्रस्तुत किए।प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा (Cooperative and Competitive Federalism) की अवधारणा को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब सभी राज्य समान रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदारी करें। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी रोजगार सृजन से जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया।आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के विकास की अगली छलांग रोजगार और कौशल विकास पर निर्भर करेगी। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों की विकास रणनीति तय करने का मंच भी बनी। बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

- रोजगार और कौशल विकास पर जोर
- विकसित भारत के लिए केंद्र-राज्य सहयोग

पीएम मोदी बोले- तकनीक और योजनाओं से बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

केंद्र सरकार की किसान-केंद्रित योजनाओं के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के योगदान को देश की समृद्धि की आधारशिला बताते हुए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं, आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसान खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। सरकार के अनुसार, करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।

भारत को सस्ते तेल की पेशकश से बदले समीकरण

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा रूस से जुड़े संस्थानों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने भारत सहित अपने प्रमुख साझेदार देशों को रियायती दरों पर तेल आपूर्ति जारी रखने का संकेत दिया है। इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और भारत की ऊर्जा रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का एक नया पैकेज घोषित किया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उन कंपनियों और संस्थाओं पर दबाव बढ़ाना है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों से जुड़ी मानी जाती हैं। रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न देशों की कई कंपनियां इन प्रतिबंधों के दायरे में आई हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेनदेन और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।दूसरी ओर, रूस ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को बनाए रखने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है। इसका लाभ भारतीय रिफाइनरियों और घरेलू बाजार दोनों को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस द्वारा दी जा रही छूट ने भारत को ऊर्जा लागत नियंत्रित रखने में मदद की है।

तेजस Mk1A प्रोजेक्ट में बड़ा खुलासा HAL ऑडिट में 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी मिलीं

भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के आंतरिक ऑडिट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस Mk1A परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए कुछ पुर्जों की 199 टेस्ट रिपोर्ट कथित रूप से फर्जी पाई गई हैं। इस खुलासे के बाद HAL ने हैदराबाद स्थित एक वेंडर कंपनी के खिलाफ बेंगलुरु में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आने के बाद रक्षा क्षेत्र और सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है।जानकारी के अनुसार, तेजस Mk1A कार्यक्रम के लिए विभिन्न पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान कई गंभीर विसंगतियां सामने आईं। ऑडिट टीम को संदेह हुआ कि कुछ रिपोर्टें वास्तविक परीक्षण के बिना तैयार की गई थीं। जांच में कुल 199 ऐसी रिपोर्टें मिलीं जिन्हें संदिग्ध या फर्जी माना गया है।HAL ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कंपनी ने संबंधित सप्लाई चेन की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन रिपोर्टों से जुड़े पुर्जे विमान निर्माण प्रक्रिया में किस स्तर तक उपयोग किए गए। आवश्यकता पड़ने पर सभी संबंधित उपकरणों और पार्ट्स का पुनः परीक्षण कराया जाएगा।तेजस Mk1A भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। ऐसे में गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को बेहद गंभीर माना जा रहा है।रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य विमानों में उपयोग होने वाले प्रत्येक पुर्जे की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। यदि परीक्षण रिपोर्टों में धोखाधड़ी हुई है, तो यह केवल एक व्यावसायिक अनियमितता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बन जाता है।

'सच बोलूं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा'

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले की काफी जानकारी है, लेकिन वह फिलहाल सच बोलने की स्थिति में नहीं हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।अपने पैतृक गांव विश्नोहरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, अगर सच बोल दूं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा।" हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिया और न ही किसी आरोप की प्रत्यक्ष पुष्टि की, लेकिन उनकी टिप्पणी ने विवाद को और चर्चा में ला दिया है।पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर में मिलने वाले दान और चढ़ावे के उपयोग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस चल रही है। विपक्षी दलों ने पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका है, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी वित्तीय प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होती हैं और चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है। उनका दावा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है।

मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा उनके नामांकन को खारिज किए जाने को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। इस याचिका के बाद राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी की निगाहें अब सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं।याचिका में कहा गया है कि नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और चुनाव अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों का सही मूल्यांकन नहीं किया। कांग्रेस का दावा है कि उम्मीदवार ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया था, इसके बावजूद उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि यह फैसला विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मुकाबले से बाहर करने का प्रयास है।राजनीतिक विश्लेषकों के

अनुसार, नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राज्यसभा की तीसरी सीट पर भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की निर्विरोध जीत लगभग तय मानी जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल दिया है। यदि अदालत नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि पाती है, तो चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनावी नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हार को कानूनी विवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है।इस मामले का फैसला केवल एक उम्मीदवार के भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर के अधिकारों और नामांकन जांच की सीमाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञों की भी नजर बनी हुई है।

हिन्दी जगत महामंच
www.tvbharatvarsh.in
tv भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर
प्रदेश का नं. 1
प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2- 3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

मेगा DSC भर्ती पर घमासान

जगन ने नायडू सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप

आंध्र प्रदेश में मेगा DSC शिक्षक भर्ती को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार को घेरा है। वहीं राज्य सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बताया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी (DSC) भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चंद्रबाबू नायडू सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं ने लाखों युवाओं के सपनों और भरोसे को झटका पहुंचाया है। ताडेपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि शिक्षक भर्ती जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सामने आ रही जानकारियां बेहद चिंताजनक हैं। यह भर्ती सिर्फ नौकरियां देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। आज डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी (DSC) के बारे में सामने आ रही सभी बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। CM एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने घोटालों के जरिए लाखों उम्मीदवारों के भरोसे को तोड़ा है और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है।' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि DSC परीक्षा लाखों युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता है। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो इसका सीधा असर उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा, 'इससे पहले कहीं भी भर्ती की इतनी खराब प्रक्रिया नहीं देखी गई है। DSC लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। भर्ती की ऐसी प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का सहारा लेना बेहद निंदनीय है। जगन ने आरोप लगाया कि सरकार को युवाओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई।' प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर झूठ, धोखेबाजी, विश्वासघात, पीठ में छुरा घोंपने और घोटालों को शर्ट-पैंट पहना दी जाए, तो वे एन. चंद्रबाबू नायडू ही होंगे। हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर चुकी है। 31 मई को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कोना शशिधर ने स्पष्ट कहा था कि मेगा DSC भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई। करीब 6 साल बाद आयोजित यह परीक्षा TCS iON प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए कराई गई। उनके अनुसार, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में सामने आए आरोप क्षैतिज आरक्षण नियमों को लेकर फैली गलतफहमी का परिणाम हैं।

जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, 2030 तक 1.5 डिग्री सीमा पार होने की आशंका

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

वैश्विक तापमान को लेकर जारी एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान गति से जारी रहा तो दुनिया वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा पार कर सकती है।वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव गतिविधियों के कारण होने वाली गर्मी बढ़ने की दर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे चरम मौसम घटनाओं, सूखे, बाढ़ और समुद्र के बढ़ते स्तर जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और जल संसाधनों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।रिपोर्ट के अनुसार कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन मौजूदा प्रयास अभी पर्याप्त नहीं हैं। विशेषज्ञों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाने की सिफारिश की गई है।संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न पर्यावरण संगठनों ने भी देशों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेज कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि आने वाले चार-पांच वर्ष वैश्विक जलवायु नीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियां और अधिक गंभीर रूप ले सकती हैं।

100 से ज्यादा घातक कामिकाज़े ड्रोन डिलीवर भारतीय सेना को मिली बड़ी ताकत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। एक के बाद एक सेना कई घातक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इस बीच भारतीय सेना को एक और बड़ी ताकत मिली है। SMPP कंपनी ने भारतीय सेना को 100 ऑपरेशनल और 6 ट्रेनिंग "पीसकीपर (अग्निवेग)" जेट-आधारित कामिकाजे ड्रोन सौंप दिए हैं। ये ड्रोन दुश्मन पर तेज गति और सटीकता के साथ घातक हमला करने में सक्षम हैं। इनके शामिल होने से भारतीय सेना की ड्रोन पॉवर में बड़ा इजाफा हुआ है। भारतीय सेना की मारक क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिला है। भारतीय रक्षा कंपनी SMPP ने सेना को 106 जेट-आधारित "पीसकीपर (अग्निवेग)" कामिकाज़े ड्रोन सौंपने का काम पूरा कर लिया है। इसमें 100 ऑपरेशनल ड्रोन और 6 ट्रेनिंग सिस्टम शामिल हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, पीसकीपर (अग्निवेग) एक स्वदेशी रूप से तैयार किया गया ड्रोन है और इसकी मारक क्षमता 180 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये कामिकाजे ड्रोन 450 किमी/घंटा तक की रफ्तार और 5 मीटर से कम CEP सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि अग्निवेग एक स्वदेशी टर्बोजेट कामिकाज़े ड्रोन है, जो दुश्मन के इलाके में 180 किलोमीटर तक अंदर जाकर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि परीक्षणों में इसका CEP 5 मीटर से भी कम रहा। साथ ही यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग जैसे आधुनिक युद्धक माहौल में भी प्रभावी ढंग से मिशन पूरा करने में सक्षम है।

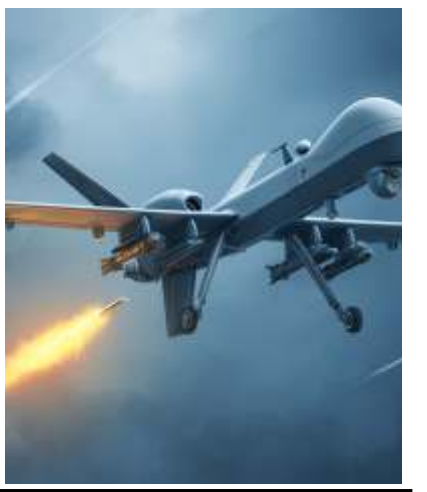

इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से दुर्लभ ओरंगुटान आबादी को बड़ा नुकसान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

इंडोनेशिया में पिछले वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का असर अब वन्यजीवों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। एक नई पर्यावरणीय रिपोर्ट के अनुसार इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुर्लभ तपनुली ओरंगुटान प्रजाति की लगभग 7 प्रतिशत आबादी समाप्त हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नुकसान केवल एक प्रजाति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है।रिपोर्ट में बताया गया है कि सुमात्रा द्वीप में आए भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण कम से कम 58 तपनुली ओरंगुटान मारे गए। यह प्रजाति दुनिया की सबसे दुर्लभ वनमानुष प्रजातियों में गिनी जाती है और इसकी कुल संख्या लगभग 800 बताई जाती है। सीमित आबादी के कारण प्रत्येक मृत्यु इस प्रजाति के अस्तित्व पर सीधा प्रभाव डालती है।पर्यावरण संगठनों ने इस नुकसान के लिए बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि जंगलों के लगातार कम होने से प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव और अधिक विनाशकारी हो रहा है। वन क्षेत्रों के सिकुड़ने से ओरंगुटानों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हुआ है, जिससे उनके लिए भोजन और सुरक्षित आश्रय की समस्या भी बढ़ गई है।विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह प्रजाति भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर सकती है। कई वैज्ञानिकों ने सरकार से संरक्षित वन क्षेत्रों का विस्तार करने और अवैध कटाई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंडोनेशिया सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने तथा वन्यजीवों की निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों का मानना है कि तपनुली ओरंगुटान को बचाने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते प्रभावी संरक्षण उपाय लागू किए गए तो इस दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है और सुमात्रा के जैव विविधता संपन्न जंगलों को भी संरक्षित रखा जा सकेगा।

जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले ईरान और यूक्रेन संकट पर बढ़ी वैश्विक चिंता

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फ्रांस में 15 जून से शुरू होने जा रहे जी-7 शिखर सम्मेलन से पहले ईरान और यूक्रेन के मुद्दे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में आ गए हैं। विश्व के प्रमुख देशों के नेताओं के बीच इन दोनों संकटों को लेकर व्यापक चर्चा की तैयारी चल रही है।फ्रांस सरकार ने संकेत दिया है कि सम्मेलन का प्रमुख फोकस मध्य पूर्व की स्थिति और रूस-यूक्रेन युद्ध रहेगा। हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल हो सकते हैं। वहीं यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से सैन्य और आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है।सूत्रों के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सम्मेलन से जुड़े कई नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। यूरोपीय देश चाहते हैं कि रूस के खिलाफ सामूहिक दबाव बनाए रखा जाए, जबकि मध्य पूर्व में संघर्ष को और बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जाएं। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य संकट से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।विश्लेषकों का मानना है कि जी-7 सम्मेलन इस वर्ष केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने, रक्षा समन्वय बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों की भी योजना है, जिनमें व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। सम्मेलन के नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसके निर्णय आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं।

संपादक की कलम से

भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता ही युवाओं का विश्वास:

देश में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाएं केवल रोजगार का माध्यम नहीं हैं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य की आधारशिला भी हैं। ऐसे में जब किसी भर्ती प्रक्रिया पर अनियमितताओं या पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते हैं, तो उसका प्रभाव केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युवाओं के मनोबल और व्यवस्था में उनके विश्वास पर भी पड़ता है। आंध्र प्रदेश की मेगा DSC शिक्षक भर्ती को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।भारत में लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई अभ्यर्थी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने करियर के लिए इन परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है, तो युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित हो।हाल के वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। प्रश्नपत्र लीक, तकनीकी गड़बड़ियां, आरक्षण नियमों को लेकर भ्रम और चयन प्रक्रिया पर उठे सवालों ने बार-बार व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। हालांकि तकनीक के बढ़ते उपयोग ने कई सुधार भी किए हैं, लेकिन केवल डिजिटल माध्यम अपनाना ही पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रभावी निगरानी तथा शिकायत निवारण तंत्र भी उतना ही आवश्यक है।राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं को राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बनने से बचाना चाहिए। यदि किसी प्रक्रिया पर आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप भी युवाओं में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों के आधार पर ही अपनी बात रखें।देश की युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था न केवल योग्य उम्मीदवारों को अवसर देती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे को भी मजबूत बनाती है। युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और यही सोच हर नीति तथा निर्णय का आधार बननी चाहिए।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में जुटे मुख्यमंत्री

'विकसित भारत 2047' पर बड़ा मंथन

भारत सरकार ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने की पहल तेज कर दी है।इसी उद्देश्य से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकास, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। बैठक में 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया।बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा जब सभी राज्य विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी निभाएं। उन्होंने राज्यों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों दोनों की है।बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। कई राज्यों ने रोजगार के अवसर बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग की मांग की। राज्यों ने कौशल विकास, कृषि आधुनिकीकरण और शहरी विकास से जुड़ी चुनौतियों को भी बैठक में उठाया।सूत्रों के अनुसार बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विशेष चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि अगले दो दशकों में भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है।राजनीतिक दृष्टि से भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में दीर्घकालिक विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों ने जहां बैठक में विकास के मुद्दों पर सहयोग की आवश्यकता बताई, वहीं कुछ नेताओं ने राज्यों की वित्तीय मांगों को प्राथमिकता देने की बात कही।विश्लेषकों का मानना है कि नीति आयोग की यह बैठक आने वाले वर्षों की विकास रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि केंद्र और राज्य मिलकर साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। बैठक से यह स्पष्ट संदेश गया कि केंद्र सरकार दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लेकर गंभीर है और राज्यों को इस अभियान का प्रमुख भागीदार बनाना चाहती है।

कांग्रेस की आपात बैठक में संगठनात्मक बदलावों पर मंथन, राज्यों में सक्रियता बढ़ाने पर जोर

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, राज्यों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल के चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किए बिना भाजपा के मुकाबले प्रभावी राजनीतिक चुनौती पेश करना कठिन होगा। इसी कारण प्रदेश इकाइयों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर सहमति बनी। नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर जनसंपर्क अभियान चलाने की रणनीति तैयार की। साथ ही पार्टी के डिजिटल अभियान को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों में संगठनात्मक फेरबदल पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नेतृत्व को अधिक जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आने वाले महीनों में संगठनात्मक पुनर्गठन और जनआंदोलनों के माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही भविष्य की चुनावी सफलता की कुंजी साबित होगा।

कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी NEET-UG परीक्षा और महंगाई के मुद्दों को "पूरी ताकत" से उठाना जारी रखेगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी NEET-UG परीक्षा, CBSE OSM और महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों को "पूरी ताकत" से उठाना जारी रखेगी। यह बात गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल संगठनात्मक बैठक के बाद कही गई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए AICC महासचिव, राज्य प्रभारी और PCC अध्यक्ष शामिल हुए थे। एएनआई से बात करते हुए शैलजा ने कहा कि जनता की परेशानियों को सामने लाना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है और वह देश भर में "दर्द और तकलीफ" से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़ोरदार आवाज़ उठाई है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। लोगों के दर्द और तकलीफ को उजागर करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम पूरे देश में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। हमें NEET, CBSE और महंगाई जैसे सभी मुद्दों पर बात करनी होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बोम्मा महेशकुमार गौड़, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर और पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी शामिल हुए। यह बैठक सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि INDIA ब्लॉक की पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पर तालमेल बेहतर करने और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के मकसद से हर दो महीने में बैठक करेंगी। खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 पार्टियां शामिल हुईं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "इस बात पर सहमति बनी कि INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां हर दो महीने में बैठक करेंगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। खड़गे ने कहा कि INDIA ब्लॉक की पार्टियों ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), "वोट की लूट" और चुनावी गड़बड़ियों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया है।

गांव की स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन आंदोलन तेज करने की चेतावनी

हुब्बल्ली तालुक के बुदरसिंगी गांव स्थित सरकारी कन्नड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय को केपीएस मैग्नेट योजना के तहत बंद कर दूसरी स्कूल में विलय किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को ग्रामीणों, अभिभावकों, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सरकार से स्कूल को यथावत संचालित रखने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सार्वजनिक शिक्षा बचाओ जिला समिति के उपाध्यक्ष शरणबसव गोनवार ने कहा कि सरकार एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर केपीएस स्कूलों की स्थापना कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से संचालित सरकारी विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों के शिक्षा अधिकार के खिलाफ है। गोनवार ने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के वंचित और गरीब वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए संघर्ष किया था। इसी उद्देश्य से गांव-गांव में सरकारी विद्यालय खोले गए थे, लेकिन अब उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि गांव की स्कूलों को बंद करने का सबसे अधिक असर गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों पर पड़ेगा। बुदरसिंगी गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित अतरगुंची केपीएस स्कूल जाना पड़ेगा, जो छोटे बच्चों के लिए बेहद कठिन होगा। अधिकांश अभिभावक मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं और उनके लिए बच्चों को रोजाना इतनी दूर भेजना आसान नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि स्कूल बंद हुई तो कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे।सार्वजनिक शिक्षा बचाओ समिति की उपाध्यक्ष गंगा जे. हुक्किनकेरी ने भी सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बुदरसिंगी गांव में यही एकमात्र सरकारी विद्यालय है और इसके बंद होने के बाद बच्चों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर दूसरी स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा, जिससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को जोखिम में डालना उचित नहीं है।प्रदर्शन के अंत में ग्रामीणों ने गांव की स्कूल को बचाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा बचाओ समितियों का गठन किया और आंदोलन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान मुल्ला साब सैदन्नवर, हीना कौसर एम. सैदन्नवर, अंजुमा एच. मुंदिनमनी, शेकप्पा जगलूर, सुभाष जगलूर सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल बचाने की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती।

सर्वे के अनुसार 76 प्रतिशत युवा अपनी शर्तों पर बिना तनाव और दबाव के बॉस बनना चाहते

बंद कमरों में होने वाली मीटिंग और पुराना कॉर्पोरेट कल्चर का दौर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। दुनियाभर के युवा प्रोफेशनल अब सफलता, लीडरशिप और ऑफिस के माहौल की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। डेलॉयट (Deloitte) के हालिया ग्लोबल सर्वे में यह बात सामने आई है कि, जेन जेड (Gen Z) और मिलेनियल्स अब पुरानी कॉर्पोरेट कल्चर को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। 44 देशों के 22,500 से ज्यादा युवाओं पर किए गए इस सर्वे ने कंपनियों और एचआर (HR) लीडर्स को एक साफ संदेश दिया है कि, भविष्य का वर्कफोर्स बड़ा बदलाव चाहता है। यह एक आम धारणा है कि, आज के युवा कम महत्वाकांक्षी हैं और लीडरशिप की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लेकिन सर्वे इस बात को गलत साबित करता है। आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 76 परसेंट जेन जेड और 67 परसेंट मिलेनियल्स अपने करियर में सीनियर या एग्जीक्यूटिव पदों पर पहुंचना चाहते हैं। हालांकि केवल 6 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनका, एकमात्र लक्ष्य सिर्फ कॉर्पोरेट की सीढ़ी चढ़ना है। युवा जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं लेकिन वे नहीं चाहते कि, सफलता की कीमत उन्हें लगातार स्ट्रेस और थकान के रूप में चुकानी पड़े। सर्वे में शामिल लगभग 50 परसेंट जेन जेड और 49 परसेंट मिलेनियल्स का मानना है कि, बड़े पदों का सीधा मतलब लगातार तनाव और मानसिक थकान (बर्नआउट) है। इसके अलावा आधे लोगों ने ज्यादा जिम्मेदारियों को और 41 से 46 परसेंट युवाओं ने खराब वर्क लाइफ बैलेंस को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया। संदेश साफ है कि अब सिर्फ अच्छी सैलरी ही काफी नहीं है। युवा कर्मचारी ऐसा काम चाहते हैं जहां, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिले और करियर ग्रोथके साथ मानसिक स्वास्थ्य से कोई समझौता न करना पड़े।

23 साल बाद बना शर्मनाक रिकॉर्ड 0 पर गिरे 3 विकेट

मैथ्यू शॉर्ट, कूपन कनोली और मैट रेनशॉ का खाता भी नहीं खुला

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम भी कमाल कर रही है। कभी बिना कोई रन बनाए टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज आउट हो गए और इसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने आकर शानदार अर्धशतक पूरा किया। इन दो बल्लेबाजों के अर्धशतक से जहां एक ओर टीम मजबूत हो गई, वहीं अब से करीब 20 साल पुरानी यादें भी ताजा हो गईं। ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सात और उससे नीचे खेलने वाले दो बल्लेबाजों ने लंबे समय बाद 50 से अधिक रन बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त बांग्लादेश दौरे पर है। सीरीज के पहले मैच में ही बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया और सीरीज में बढ़त बना ली। इसके बाद जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो पारी का आगाज बहुत ही खराब हुआ। टीम के तीन बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन टीम का एक भी रन नहीं बना था। मैथ्यू शॉर्ट, कूपन कनोली और मैट रेनशॉ बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद कई बल्लेबाजों ने टीम को मजबूती देने की कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। आखिर में मार्नस लाबुशेन और जेवियर बार्टलेट ने अर्धशतक पूरा किया। मार्नस नंबर 7 और जेवियर बार्टलेट नंबर आठ पर बल्लेबाजी के लिए आए। लाबुशेन ने 85 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। इसमें तीन चौके शामिल रहे। वहीं जेवियर बार्टलेट ने 48 बॉल पर तेजी से 52 रन बनाए। इसमें चार चौके और दो छक्के उनके बल्ले से आए। ऑस्ट्रेलिया के वनडे इतिहास में ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है, जब टीम के सातवें और उससे नीचे आने वाले बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रन बनाए हों। पहली बार साल 1994 में ऐसा हुआ था। तब शेन वार्न और पॉल राइफल ने काफी नीचे आकर अर्धशतक लगाया था। इसके बाद साल 2006 में माइक हसी और ब्रेट ली ने भी अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी। यानी करीब 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल टीम के टॉप बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, इसलिए नीचे के बल्लेबाजों के पास मौका बना, जिसका उन्हें फायदा उठा लिया। लेकिन टीम फिर भी बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को जाना और पहचाना जाता है।

हर्षा भोगले ने वैभव की तारीफ की

वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ दांबुला के रांगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम महज 22 गेंदों पर 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि शुरुआत से ही छक्कों के लिए मशहूर इस 15 साल के टीनएजर ने अपनी इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने गेंदबाजों से सिर्फ चौकों में ही डील की। इस दौरान उनके बल्ले से 9 चौके आए, जिसके लिए प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनकी पीठ थपथपाई है। लेकिन हर्षा को एक बात का मलाल रह गया कि वह वैभव की ये पारी नहीं देख पाए। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले करने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बिना समय गंवाए विरोधी टीम पर अटैक किया। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अफगानिस्तान के सीमर की किसी भी ढीली गेंद को चौके के लिए भेजा। इस युवा खिलाड़ी के आक्रामक रवैये ने इंडिया ए को सिर्फ पांच ओवर में बिना किसी नुकसान के 50 रन बनाने में मदद की। उन्होंने बार-बार ऑफ साइड में गैप ढूंढे। साथ ही शॉर्ट-पिच बॉलिंग पर हावी होने की अपनी काबिलियत भी दिखाई। प्रभसिमरन सिंह के साथ उनकी 74 रन की पार्टनरशिप ने पारी की मजबूत नींव रखी। एक समय ऐसा लग रहा था कि वैभव आसानी से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन अब्दुल्ला अहमदजई ने 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान ए को ब्रेकथ्रू दिलाया। दरअसल, सूर्यवंशी शॉर्ट डिलीवरी पर रैंप शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को विकेटकीपर इशाक रहीमी के हाथों में थमा बैठे। इस शॉट से खुद वैभव निराश नजर आए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 22 बॉल तक चली तूफानी पारी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और मोमेंटम को पूरी तरह से भारत ए के पक्ष में कर दिया।

फीफा विश्व कप 2026 का आगाज, मेक्सिको में होगा उद्घाटन मुकाबला

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का आगाज होने वाला है। पहले 6 जून से टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 13 जून से तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस बीच अचानक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पता चला है कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा है। विराट कोहली लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए खेलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन खुद कोहली और उनके फैंस को करारा झटका लगा है। अब विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। विराट कोहली अभी कुछ दिन पहले तक आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल रहे थे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में कोहली ने धमाकेदार पारी खेली थी और छक्का लगाकर अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। बीसीसीआई के एक सोर्स ने PTI को बताया कि कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण ODI सीरीज से बाहर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में आने वाली सीरीज की चमक फीकी पड़ जाएगी। हालांकि भारत के पूर्व कप्तान कोहली अब एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन वह दुनिया भर के फैंस के लिए टॉप अट्रैक्शन बने हुए हैं। अभी उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। आईपीएल खत्म होने के बाद अहमदाबाद से कोहली सीधे आगरा पहुंचे और वहां से वृंदावन आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी थीं और दोनों ने वहां पर प्रेमानंद महाराज के दरवार में पहुंचे थे। इसकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। कोहली और अनुष्का मुंह पर मास्क लगाकर वहां पहुंचे थे, ताकि ज्यादा लोग उन्हें पहचान ना पाएं। माना ये जा रहा था कि कोहली वनडे सीरीज से पहले प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, उसने फैंस के दिल को तोड़ दिया है।

आलिया भट्ट बनीं 'ALPHA BHATT'

यशराज स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-केंद्रित फिल्म 'Alpha' का टीज़र रिलीज हो गया है। टीज़र में आलिया भट्ट का दमदार एक्शन अवतार देखने को मिला। फिल्म इंडस्ट्री से भी शानदार प्रतिक्रिया मिली है। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आलिया की तारीफ की, जबकि विक्की ने उन्हें "ALPHA BHATT" कहा।

क्यों चर्चा में?

- स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला लीड फिल्म
- आलिया का एक्शन अवतार
- सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा

ऋतिक रोशन का हॉलीवुड की ओर बड़ा कदम

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने हॉलीवुड की प्रसिद्ध मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कंपनी Anonymous Content के साथ करार किया है। यह वही कंपनी है जो Spotlight, True Detective और The Revenant जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से जुडी रही है।

क्यों महत्वपूर्ण?

- अंतराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के अवसर बढ़ेंगे
- वैधिक स्तर पर भारतीय स्टार की मौजूदगी मजबूत होगी
- फैंस को नए हॉलीवुड सहयोग देखने को मिल सकते हैं

कंगना रनौत की 'Bharat Bhhagya Viddhaata' पर नजरें

कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'Bharat Bhhagya Viddhaata' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले फिल्म चर्चा में है क्योंकि इसके OTT प्लेटफॉर्म की जानकारी भी सामने आ चुकी है। फिल्म 26/11 मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों की बहादुरी की कहानी पर आधारित है।

फिल्म की खास बातें

- सच्ची घटनाओं पर आधारित
- देशभक्ति और साहस की कहानी
- कंगना रनौत मुख्य भूमिका में

लखनऊ में बोले पीयूष गोयल, जनता फिर नकारेगी अखिलेश को

लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास और सुशासन के आधार पर निर्णय लेगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लखनऊ में आयोजित "प्रबुद्ध जन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन" में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन में आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भी दौरा किया और देश के महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। जनता न तो उनके ट्वीट्स को महत्व देती है और न ही उनके दावों पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उनके शासनकाल को देखा है और यह भी देखा है कि उस दौरान विकास की गति किस प्रकार प्रभावित हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति कमजोर रही, प्रदेश के संतुलित विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि जनता इन बातों को भूली नहीं है और आने वाले समय में भी ऐसे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बीते 12 वर्षों में आधारभूत संरचना, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, सड़क निर्माण, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। सम्मेलन में प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। यदि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तो भारत की प्रगति भी स्वतः तेज होती है। उन्होंने कहा कि यह वह भूमि है जहां कबीर, तुलसीदास और रविदास जैसे महान संतों ने समाज को नई दिशा दी। हिंदी और उर्दू जैसी समृद्ध भाषाओं की जड़ें भी इसी प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने विकसित भारत के विजन को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। वक्ताओं ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को आवश्यक बताया। सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्धजनों से भी राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया गया।

KGMU में नोटिस पाने वाली ANS के फेयरवेल पर विवाद

KGMU के नेत्र रोग विभाग में ड्यूटी में कथित कोताही के मामले में नोटिस और तबादले के बीच विभागीय फेयरवेल पार्टी की तैयारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप हैं कि बाहरी लैंस, दवाएं और बाकी का सामान पहुंचने से रोकने में नाकाम रहने पर ओटी में तैनात A N S (असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट) को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया गया। अब विभाग की ओर से उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। नेत्र रोग विभाग में गुरुवार शाम तीन बजे फेयरवेल पार्टी रखी गई है। इसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। खास बात यह है कि विभागाध्यक्ष की ओर से बाकायदा नोटिस जारी कर समारोह की जानकारी साझा की गई है। KGMU के नेत्र रोग विभाग में बाहर से मरीजों को लैंस और दवाएं लिखे जाने के आरोपों के बाद एक डॉक्टर को निलंबित किया जा चुका है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में बाहरी लैंस, दवाओं और दूसरे सामान के प्रवेश को लेकर भी सवाल उठे थे। मामले में ओटी इंचार्ज की जिम्मेदारी तय करते हुए ANS को नोटिस जारी किया गया था।

नया हनुमान मंदिर क्षेत्र का बदलेगा स्वरूप, हटाई गईं 10 दुकानें

लखनऊ के अलीगंज स्थित नया हनुमान मंदिर के सामने वर्षों से लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने गुरुवार को अभियान चलाकर सड़क किनारे बनी 10 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। छह दुकानों को हटाने के लिए शुक्रवार को फिर कार्रवाई की जाएगी। अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष रूप से जेठ माह के बड़े मंगल पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास करीब 250 मीटर का हिस्सा लंबे समय से यातायात की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मंदिर से पहले सड़क फोरलेन है, लेकिन मंदिर के सामने पहुंचते ही सड़क संकरी हो जाती है, जिससे रोजाना जाम लगता है। बड़े मंगल और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। PWD की योजना के तहत मंदिर के सामने वाली पट्टी पर सड़क को करीब 10 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। हालांकि इस हिस्से में 16 पक्की दुकानें और कुछ निर्माण मौजूद थे, जिसके चलते परियोजना अटकी हुई थी। विभाग की ओर से पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस के बाद कुछ लोगों ने स्वयं दुकानें खाली कर दी थीं। गुरुवार को विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर 10 दुकानों को हटा दिया। अधिकारियों के अनुसार बाकी छह दुकानों को भी हटाने के बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा। सड़क चौड़ी होने से मंदिर क्षेत्र में लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

हजरतगंज में ब्यूटी पार्लर में लगी आग

हजरतगंज के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर में गुरुवार सुबह आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची। पार्लर से ऊपर की छत पर 2 लोग धुएं से घिर गए थे। फायरकर्मियों ने उन्हें सीढ़ी लगाकर सुरक्षित नीचे उतरवा लिया। इस दौरान आग लगातार बुझाई जा रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ गई, लेकिन पार्लर का सारा सामान पूरी तरह से जल चुका था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह 5:42 बजे फायर स्टेशन हजरतगंज कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि 'जस्ट फॉर डिवाइस' केडीए पार्लर में आग लग गई है। सूचना मिलते ही हजरतगंज फायर स्टेशन से तीन फायर टेंडर और चौक फायर स्टेशन के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पुष्पेंद्र यादव टीम के साथ मौके पर रवाना हुए। दमकलकर्मियों के पहुंचने पर पता चला कि आग भवन के भूतल पर स्थित पार्लर में लगी थी, जबकि ऊपर के दोनों तल आवासीय थे। आग से निकले धुएं के कारण भवन में रह रहे हफीज उल्ला और शादाब खान छत पर पहुंच गए थे। फायरकर्मियों ने तत्काल सीढ़ी लगाकर दोनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। फायर टीम ने मोटर फायर इंजन से पंपिंग शुरू कर आग बुझाने का अभियान चलाया। इसके बाद स्मोक एग्जॉस्टर की मदद से पूरे भवन से धुआं बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मकान मालिक के मुताबिक, आग भूतल पर संचालित पार्लर में लगी थी। पार्लर की संचालिका दीपिका राठौड़ हैं। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पार्लर में रखा सामान जल गया।

'खेत बचाओ अभियान' के तहत किसानों को टिकाऊ खेती का दिया गया संदेश

लखनऊ के विकास खंड चिनहट स्थित मेहोर और जुग्गौर गांव में गुरुवार को भारत सरकार के 'खेत बचाओ अभियान' के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और खेती योग्य भूमि के लगातार कम होते रकबे को देखते हुए किसानों को कृषि भूमि संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में किसानों को उपजाऊ जमीन बचाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सहायक विकास अधिकारी (कृषि), चिनहट, अभिलाषा सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि देश की अमूल्य धरोहर है और इसका संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरकों के उपयोग, जल संरक्षण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।

भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराया, रातभर परेशान रहे लखनऊवासी

लखनऊ भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट भी बरकरार है। बुधवार देर रात भी शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। कुर्सी रोड स्थित सृष्टि उपकेंद्र के तहत आने वाले गुडंबा, जानकीपुरम गार्डेन और निर्मल होम्स जैसे बड़े इलाकों में रात 9 बजे से ही बिजली की ट्रिपिंग शुरू हो गई जो देर रात तक जारी रही। पीजीआई के एकता नगर में पानी प्लांट के पास शाम को ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे देर रात तक बड़े इलाके में अंधेरा छाया रहा। रायबरेली रोड स्थित बंगाली टोला में बिजली का खंभा गिर गया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने उपकेंद्र पर फोनकर बिजली बंद कराई। निलमथा विजयनगर के यूनियन बैंक के पास रात 12:30 बजे बिजली के खंभे में आग लग गई। इससे डेढ़ घंटे इलाके में अंधेरा रहा। कुर्सी रोड में लाइट नहीं आई तो टोल फ्री नंबर 1912 और उपकेंद्र पर शिकायत की गई। इससके बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो रात करीब 12:30 बजे गुस्साई भीड़ सृष्टि उपकेंद्र पहुंच गई। लोगों ने वहां विरोध और हंगामा किया। लोगों के विरोध और नाराजगी के बाद रात 2:30 बजे बिजली बहाल हो सकी। अधिशासी अभियंता अरुण कुमार भारती के मुताबिक, यह समस्या 33 केवी लाइन में आए फॉल्ट के कारण हुई थी। इसके अलावा न्यू कैंपस उपकेंद्र के मुस्लिम नगर और कोटवा में भी लोग बिजली की ट्रिपिंग से पूरी रात परेशान रहे। आलमबाग के आजाद नगर और तिवारीगंज की नई बस्ती में शॉर्ट सर्किट से केबल जलने के कारण घंटों अंधेरा छाया रहा।

मानसून से पहले प्रशासन अलर्ट,

उन्नाव में आपदा प्रबंधन का रिहर्सल

उन्नाव में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए गुरुवार को गंगा तट स्थित आनंद घाट पर एक व्यापक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार गोंड के नेतृत्व में हुए इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। मॉकड्रिल के दौरान बाढ़ और नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी बाढ़ दल की टीमों ने मोटरबोट तथा अन्य उपकरणों का उपयोग कर बचाव अभियान चलाया। इसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने का प्रदर्शन किया गया। बचाव कार्य के बाद, प्रभावित लोगों को मिश्रा कॉलोनी में स्थापित एक राहत शिविर में ठहराने की व्यवस्था का प्रदर्शन किया गया। शिविर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग पंजीकरण काउंटर तथा पृथक आवासीय कक्ष बनाए गए थे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से गर्म भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी प्रदर्शित की गई। मॉकड्रिल में नदी में नाव पलटने की एक काल्पनिक घटना भी दर्शाई गई। इसमें डूब रहे ग्रामीणों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार प्रदान किया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का भी सफल प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त, एक औद्योगिक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की स्थिति का भी अभ्यास किया गया। पुलिस विभाग ने अग्निशमन वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया, जबकि अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रदर्शन किया। राहत शिविर में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कैंप, शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक शिक्षा केंद्र और बाल क्रीड़ा केंद्र, पुलिस ने कंट्रोल रूम, जल निगम ने स्वच्छ पेयजल व्यवस्था तथा स्वास्थ्य विभाग ने संक्रामक रोग नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का प्रदर्शन किया। इस मॉकड्रिल में राजस्व विभाग, पुलिस, सिंचाई विभाग, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी बाढ़ दल, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, जल निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, नागरिक सुरक्षा, एनसीसी, एनएसएस और आपदा मित्रों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। एडीएम सुशील कुमार गोंड ने कहा कि आपदा के समय सभी विभागों के बीच समन्वय और त्वरित कार्रवाई ही जनहानि को कम कर सकती है। मॉकड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना है।

डंपर की टक्कर से जीजा-साली की मौत

उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में जीजा-साली की मौत हो गई। पुरवा-मलौना लिंक मार्ग पर भदिया गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक के पास खड़े दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मंशाखेड़ा गांव निवासी बिटोल (40) पत्नी रामकिशुन पासी और दिलीपशाह खेड़ा, गोजहरी, थाना गुरुबक्शगंज, रायबरेली निवासी प्रेमशंकर (55) पुत्र स्व. रामनरेश के रूप में हुई है। दोनों पुरवा स्थित एक बैंक जा रहे थे। भदिया गांव के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी थी, तभी डंपर ने उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक डंपर सहित मौके से फरार हो गया।सूचना मिलने पर बिहार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। मृतक प्रेमशंकर और बिटोल रिश्ते में जीजा-साली थे। दोनों की एक साथ मृत्यु से उनके परिवारों में शोक का माहौल है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मृतका बिटोल अपने पीछे चार बेटियां और तीन बेटे छोड़ गई हैं। प्रेमशंकर की पत्नी रामा देवी भी इस घटना से सदमे में हैं।

उन्नाव लूटकांड: 'गोली चली, फिर भी एफआईआर में नहीं दर्ज'

उन्नाव में ज्वेलर्स से हुई 18 किलो चांदी की लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एफआईआर में संशोधन की मांग की है। उनका आरोप है कि प्राथमिकी में घटना के दौरान हुई फायरिंग और लूटी गई चांदी की वास्तविक मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे मामले की गंभीरता कम दर्ज हुई है। यह घटना औरास थाना क्षेत्र में 8 जून की शाम को हुई थी। रामपुर खझड़ी गांव निवासी ज्वेलरी कारोबारी प्रभात कुमार सोनी अपनी दुकान बंद कर करीब 18 किलोग्राम चांदी के जेवरात एक बैग में रखकर अपने छोटे भाई अतुल सोनी के साथ बाइक से घर जा रहे थे। गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले, दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने चांदी से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर एक बदमाश ने प्रभात सोनी की कनपटी पर तमंचा तान दिया, जबकि दूसरे ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। गोली उनके कान के पास से निकल गई। इसके बाद बदमाश चांदी के जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद प्रभात सोनी ने डायल-112 और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज की। हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करते समय उनकी पूरी बात नहीं सुनी गई और मनमाने ढंग से तहरीर दर्ज कर ली गई। प्रभात सोनी के अनुसार, प्राथमिकी में न तो फायरिंग की घटना का समुचित उल्लेख किया गया और न ही लूटी गई चांदी का वास्तविक वजन दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि लूटी गई चांदी के जेवरात की कीमत करीब 35 से 37 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि घटना के समय वे बेहद घबराए हुए थे, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एफआईआर में शामिल नहीं हो पाए थे। इसी कारण उन्होंने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र और प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर में संशोधन की मांग की है। प्रभात सोनी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने उन्हें मामले की जांच प्रगति पर होने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस लूटकांड में शामिल बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।

उन्नाव के शिक्षा विभाग में करोड़ों का खेल, जांच के बाद पांच पर मुकदमा

उन्नाव जनपद के पुरवा के एमआरआरएस इंटर कॉलेज में हुए करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में विद्यालय एवं शिक्षा विभाग से जुड़े पांच कर्मचारियों को वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी धन के गबन और कूटरचना का दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वरिष्ठ कोषाधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया था। समिति ने विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी, जिसमें करोड़ों रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी तरीके से खातों में धनराशि स्थानांतरित किए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रधान लिपिक अमित कुमार मिश्रा, परिचारक विनोद कुमार त्रिपाठी, परिचारक कुलदीप कुमार, लिपिक राधेश्याम तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सागर कपूर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। समिति ने इन्हें वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन सभी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। संबंधित कर्मचारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि शेष धनराशि की वसूली और अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच भी जारी है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने स्पष्ट कहा कि किसी भी विभाग में सरकारी धन के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी चाहे किसी भी पद पर हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जांच समिति के अनुसार प्रधान लिपिक अमित कुमार मिश्रा के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 2.68 करोड़ रुपये तथा अन्य कर्मचारियों के खातों में भी लाखों रुपये स्थानांतरित किए गए। प्रारंभिक जांच में कुल 3.01 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला सामने आया है। समिति का मानना है कि धनराशि को सुनियोजित तरीके से विभिन्न खातों में भेजा गया। रिपोर्ट में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सागर कपूर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच में पाया गया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए तथा अधिकारियों के डिजिटल डोंगल का गलत इस्तेमाल कर वित्तीय प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। इसे समिति ने सुनियोजित कूटरचना और गबन की साजिश का हिस्सा माना है।

उन्नाव में खेत विवाद में महिलाओं-बच्चों समेत 12 लोग घायल

उन्नाव जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट, पथराव और कुल्हाड़ी से हमले की इस घटना में महिलाओं और बच्चों सहित करीब 12 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घायल महिला मंजू के अनुसार, विवाद उस समय शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोग उनके खेत में जबरन लकड़ी काट रहे थे और नशा कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले गई। मंजू का आरोप है कि करीब 15 लोग एकत्र होकर गाली-गलौज करने लगे और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने महिलाओं और बच्चों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा तथा पथराव भी किया। उन्होंने बताया कि विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। घटना में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट और हंगामे जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने पुरवा कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंजू ने बताया कि पुलिस को लिखित शिकायत सौंप दी गई है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

उन्नाव में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, हाईवे पर मची अफरा-तफरी

उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र स्थित कल्लूपुरवा नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। कानपुर से लखनऊ की ओर जा रही इस ट्रक में अचानक आग लगने से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक कानपुर से लखनऊ की दिशा में जा रही थी। कल्लूपुरवा के पास पहुंचते ही ट्रक से धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जाजमऊ चौकी प्रभारी विनोद सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए हाईवे पर यातायात को रोक दिया, ताकि कोई जनहानि न हो और राहत एवं बचाव कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। पुलिसकर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया। उधर, दमकल विभाग को सूचना मिलते ही कई गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही।

पंचायत चुनाव से पहले बदला मतदाता गणित नई सूची ने उलट दिए सियासी समीकरण

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर अंतिम सूची जारी की है।इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं को जोड़ा गया है और मृतक, डुप्लीकेट व विस्थापित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।नई मतदाता सूची से कई जिलों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है, जिससे पंचायत चुनाव और अधिक रोचक हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची ने ग्रामीण सियासत के सूरमाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस बार की सूची केवल आंकड़ों का फेरबदल नहीं है, बल्कि इसने जमीन पर बरसों से जमी-जमाई राजनैतिक बिसात को हिलाकर रख दिया है। कागजों पर दिख रही यह संख्या जब गांवों की चौपालों तक पहुंची, तो चुनावी समीकरण उलटपुलट गए। पंचायत चुनाव का गणित लोकसभा या विधानसभा से बिल्कुल अलग होता है। यहां कोई लहर काम नहीं करती, बल्कि सीधा संपर्क काम आता है। लंबे इंतजार के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पंचायत चुनाव के लिए पुनरीक्षित अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। नई सूची के अनुसार उत्तर प्रदेशमें 2,32,24,805 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, जबकि 2,03,23,287 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृतक, विस्थापित, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाता शामिल हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या में 29,01,518 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब प्रदेश में कुल 12,58,51,570 मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इसके बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों पर सुनवाई कर अंतिम सूची तैयार की गई। पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 12,29,50,052 थी, जो अब बढ़कर 12,58,51,570 हो गई है। इस बार आयोग ने सभी मतदाताओं को 9 अंकों का विशेष स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। यह प्रत्येक मतदाता की विशिष्ट पहचान होगा। इस नंबर के माध्यम से मतदाता के निवास क्षेत्र, मतदान इतिहास और अन्य संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। यह नंबर किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार जारी किया जाएगा। मतदाता का नाम सूची से हटने के बाद भी यह नंबर फ्रीज रहेगा और दोबारा किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण के दौरान कई जिलों में मतदाता संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सबसे अधिक नाम आजमगढ़ और गाजीपुर में काटे गए। आजमगढ़ में 8,19,646 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि 7,59,299 नए मतदाता जोड़े गए। इसके परिणामस्वरूप जिले में कुल 60,347 मतदाता कम हो गए। अब यहां कुल मतदाताओं की संख्या 35,76,287 है, जबकि पिछली सूची में यह 36,36,634 थी। गाजीपुर में 7,15,668 नाम हटाए गए और 6,20,911 नए मतदाता जोड़े गए। इससे जिले की मतदाता संख्या 29.06 लाख से घटकर 28.11 लाख रह गई। यहां कुल 94,757 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन जिलों में बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं, वहां आगामी पंचायत चुनावों के परिणामों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। नए मतदाता स्थानीय चुनावी समीकरणों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बरेली में बृहस्पतिवार को आठ घंटे तक रोडवेज की 400 बसों का संचालन बंद रहा

शाहजहांपुर के तिलहर में बुधवार रात हुए हादसे में रोडवेज चालक की मौत के बाद रूहेलखंड व बरेली डिपो के चालकों व परिचालकों ने हड़ताल कर दी। इस दौरान आठ घंटे तक रोडवेज की 400 बसों के पहिए थम गए। उनका आरोप था कि हादसे के समय किसी उच्चाधिकारी का मौके पर फोन नहीं उठा, जिससे साथी की मौत हो गई। घटना का कारण चालक को लगातार बस चलाने से आई झपकी को बताया गया। दोपहर में आरएम व एआरएम के समझाने के बाद कर्मचारी काम पर लौटे तब जाकर बसों का संचालन शुरू हो सका। बस संचालन बंद होने से रोडवेज को करीब आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बरेली जिले के नवाबगंज तहसील के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बीसी रम्पुरा निवासी प्रमोद (30 वर्ष) रोडवेज में एक साल से संविदा चालक की नौकरी कर रहे थे। वह बुधवार की शाम बरेली से लखनऊ के लिए रोडवेज बस लेकर निकले। वापसी के समय शाहजहांपुर के तिलहर में बुधवार रात करीब तीन बजे चालक को झपकी आने से बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। बताया गया कि ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक मार दिए थे। बस की गति अधिक होने के कारण चालक घायल हो गया। घटना के बाद यात्रियों व परिचालक ने 108 एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंची। तभी उधर से गुजर रहे दूसरे रोडवेज चालक ने अपनी बस से चालक प्रमोद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। चालकों व परिचालकों का आरोप है घटना के समय किसी उच्चाधिकारियों का फोन नहीं उठा, तुरंत उपचार मिलता तो शायद प्रमोद की मौत न होती। साथी की मौत की सूचना मिलते ही बरेली के सेटेलाइट व पुराने बस अड्डे पर बरेली व रूहेलखंड डिपो की सभी बसों के चालक व परिचालक हड़ताल पर चले गए। जब सुबह सात बजे मामले की जानकारी एआरएम एके वाजपेयी हो हुई तो वह हड़ताल को समाप्त करने गए लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई।

ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर-152 में एक दर्दनाक हादसा

ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर-152 में एक दर्दनाक हादसा 11 जून को उस समय आया जब वहां पर निर्माणाधीन सोसाइटी एटीएस पिक्चरेस्क रिप्राइव में 2 मजदूरों की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। इस सोसाइटी के टावर संख्या-23 की 37वीं मंजिल पर शटरिंग का कार्य कर रहे दो मजदूर सेफ्टी बेल्ट पहने हुए थे लेकिन अचानक उसके टूट जाने से वह सीधे ऊंचाई से ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिर गए। इस दौरान दोनों ही मजदूरों को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद निर्माणाधीन सोसाइटी में काफी अफरा-तफरी भरा माहौल देखने को मिला तो वहीं घटना की सूचना मिलते नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।निर्माणाधीन सोसाइटी में काम करने के दौरान हादसे में मरने वाले दोनों मजदूरों को लेकर पुलिस के अनुसार बताया गया कि गुरूवार दोपहर करीब 12:45 बजे उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-152 स्थित निर्माणाधीन एटीएस परियोजना में कार्य के दौरान दो मजदूर ऊंचाई से गिर गए हैं। हादसे में मरने वाले दोनों मजदूरों की पहचान 24 साल के रईसुल हक निवासी जिब्रामर कुथी, फुलेश्वरी, कूच पश्चिम बंगाल और दूसरे मजदूर की पहचान अब्दुल समद उम्र 45 साल निवासी खरीजा फुलेश्वरी पुतिमारी कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है, जिसमें दोनों ही मजदूर वर्तमान में निवासी कोंडली मार्केट में रहते थे। दोनों ही मजदूर टावर संख्या-23 की 37वीं मंजिल पर शटरिंग का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगी सेफ्टी बेल्ट अचानक टूट गई, जिससे दोनों संतुलन खो बैठे और ऊंचाई से नीचे गिर गए। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों मजदूरों को गंभीर चोटें आईं। निर्माण कंपनी के कर्मचारियों और अन्य मजदूरों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए घायल दोनों ही मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण सेफ्टी बेल्ट का टूटना बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

राम मंदिर में दान राशि की कथित हेराफेरी को लेकर विवाद,पारदर्शी जांच की मांग

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की हेराफेरी का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है। भाजपा नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक शिकायती पत्र भेजा था। इस प्रकरण ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र सोमवार को अचानक अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने बंद कमरे में एक बैठक की, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, अब एक और महंत की एंट्री हो गई। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान व्यवस्था को लेकर उठे विवाद पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जांच करने वालों की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, मिश्र ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के साथ भी विस्तृत बात की। यह बैठक पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी। इसकी कार्यसूची को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। बैठक के बाद वह मंगलवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद और उसके तुरंत बाद नृपेंद्र मिश्र के इस दौरे को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि मंदिर की व्यवस्थाओं और हालिया घटनाक्रम पर तैयार होने वाली रिपोर्ट अब शीर्ष स्तर तक पहुंच सकती है। उधर, भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में पूरे मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए दान, चढ़ावे और मंदिर प्रशासन से जुड़े किसी भी आरोप की पारदर्शी जांच आवश्यक है।